उपसभाध्यक्ष महोदय, मणिमहेश, जो कि एक पवित्र हिन्दू तीर्थ स्थल है और जिसकी यात्रा अगस्त महीने मे प्रारम्भ होती है, एक बहुत कठिन यात्रा है। यह तीर्थ स्थल जिला - चम्बा, तहसील-भरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु मणिमहेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से लेकर हेलीकाप्टर, परिवहन, आवास, शौचालय एवं बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की बहुत कमी है। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत विकट है, जिसका समाधान सुंकू की टप्परी से थला चोबिआ होकर हड़सर को मिलाकर, कोउ सेरी के पुल को मजबूत बना कर और नेशनल हाईवे 154A का विस्तार करके किया जा सकता है। महोदय, इसकी समीक्षा की जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संचार, बिजली, हेलीकाप्टर, परिवहन एवं यातायात की सुचारु व्यवस्था, आवास एवं शौचालय जैसी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध तथा ट्रैफिक की समस्या का भी निवारण किया जाये। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरह ही यहाँ पर भी बोर्ड की स्थापना की जाये, जिससे यहाँ के विकास और व्यवस्था का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Nagendra Ray (West Bengal), Shri Naveen Jain (Uttar Pradesh), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Tejveer Singh (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat) and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri A.D. Singh; not present. Now, Dr. Bhim Singh.

Demand for increase in the fellowships for OBC researchers

डा. भीम सिंह (बिहार) : महोदय, भारत की विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। यह वर्ग देश की कुल आबादी का 16.6 प्रतिशत है। इस वर्ग को प्रतिवर्ष 2,000 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत यूजीसी-नेट (UGC-NET) और 25 प्रतिशत संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी (CSIR- UGC) परीक्षा के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए निर्धारित होती हैं।

14% आबादी वाले कथित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय

अध्येतावृत्ति (MANF) को यद्यपि अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर, 2022 को बंद कर दिया गया है, पर पहले इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 1,000 अध्येतावृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान था।

मैं सरकार का ध्यान देश की सबसे बड़ी आबादी (मंडल आयोग के अनुसार 52% और NSSO के अनुसार 44%) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में, ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (NFOBC) योजना के तहत प्रति वर्ष मात्र 1,000 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यह देखकर अत्यंत निराशा होती है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के लिए इतनी कम अध्येतावृत्तियों का प्रावधान है। महोदय, इसे बढ़ाया जाना समय की माँग है।

अतः, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस वर्ग के साथ न्याय सुनिश्चित करते हुए ओबीसी शोधार्थियों के लिए कम से कम 6000 अध्येतावृत्तियों की व्यवस्था की जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Bhim Singh: Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Urgent need to address train sabotage and anti-national activities

SHRI LAHAR SINGH SIROYA (Karnataka): Sir, the alarming rise in attempts to derail trains across the country poses a severe threat to public safety and national security. Recent incidents indicate coordinated efforts to target India's railway network, a vital lifeline of the nation.

In Punjab's Bathinda, nine iron rods were strategically placed on the Delhi-Bathinda Express track on September, 22nd. Similarly, large cement blocks, each weighing 70 kg, were discovered on the Ajmer-Ahmedabad railway route in Rajasthan on September, 8th, posing a significant risk of derailments. Near Kanpur, the Kalindi Express narrowly averted disaster when an LPG cylinder and explosives placed on the tracks caused an explosion.

These deliberate acts of sabotage, seemingly orchestrated by radical groups, reveal a coordinated attempt to destabilize the country. Immediate action is critical. I urge that the Government should empower the National Investigation Agency (NIA) to conduct thorough investigations into these incidents and strengthen railway security across the nation. Swift measures are essential to protect lives, restore public confidence, and uphold national integrity. The urgency for vigilance has never been greater. India cannot afford complacency in the face of such threats.